बाजार में प्याज 65 रुपए किलो तक पहुंची

चीनी और चावल की कीमतों ने भी बढ़ाई रसोई की चिंता

नवभारत न्यूज

नयी दिल्ली, 28 अगस्त त्योहारों के सीजन से पहले आम आदमी की रसोई पर महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है. प्याज, चीनी और चावल की कीमतों में तेजी ने घरेलू बजट बिगाड़ने की आशंका बढ़ा दी है. केंद्र सरकार के बफर स्टॉक में खरीदे गए 1.20 लाख टन प्याज में से करीब 36 हजार टन प्याज सड़ने और अंकुरित होने के कारण खराब हो गया है.

वहीं, खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 50 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है. बेमौसम बारिश से प्याज की शेल्फ लाइफ घटने और किसानों के पास भी स्टॉक तेजी से कम होने के कारण सितंबर-अक्टूबर में आपूर्ति संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है.

कांदा एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंचेगा सस्ता प्याज- बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने बाजार में हस्तक्षेप शुरू कर दिया है. महाराष्ट्र के लासलगांव से 500 टन प्याज लेकर पहली विशेष मालगाड़ी कांदा एक्सप्रेस दिल्ली के लिए रवाना हुई है. छंटाई और ग्रेडिंग में समय लगने के कारण ट्रेन करीब 24 घंटे की देरी से चली. दिल्ली में नैफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के आउटलेट्स के माध्यम से प्याज 35 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा. ट्रकों से भी करीब 60 टन प्याज दिल्ली पहुंचाया जा चुका है. आने वाले दिनों में चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, एर्नाकुलम और मदुरै के लिए भी विशेष ट्रेनें चलाने की योजना है.

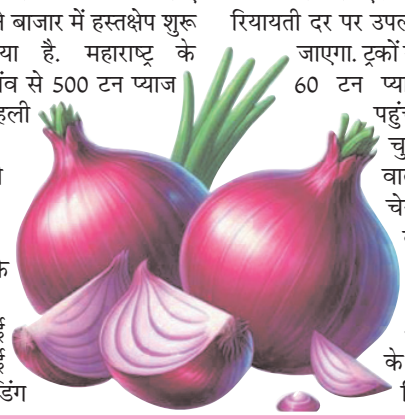

अक्टूबर में सप्लाई गैप का खतरा-गर्मियों में काटी गई प्याज आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर तक बाजार की जरूरत पूरी करती है. इस बार खरीफ प्याज की रोपाई भी बेहद कमजोर है. नासिक में सामान्य तौर पर करीब 30 हजार हेक्टेयर में खरीफ प्याज लगाया जाता है, लेकिन अब तक केवल 370 हेक्टेयर में रोपाई हो पाई है. ऐसे में नई फसल नवंबर के मध्य या दिसंबर से पहले बाजार में आने की संभावना कम है. यदि मौजूदा स्टॉक तेजी से खत्म हुआ तो सितंबर-अक्टूबर में प्याज की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है.

चीनी की कीमतों में भी उछाल

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस के मुताबिक चीनी की कीमत 45 रुपए प्रति किलो से बढ़कर अगस्त में 70-75 रुपए तक पहुंच गई है. पार्टी ने आरोप लगाया कि त्योहारों के दौरान बढ़ी कीमतों से आम लोगों पर करीब 36 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. कांग्रेस ने दावा किया कि 2025-26 का शुरुआती चीनी स्टॉक पिछले साल के 80 लाख टन के मुकाबले घटकर 50 लाख टन रह गया है.

एमपी का वाहन बाजार त्योहारों के रंग में

नवभारत न्यूज

भोपाल, 28 अगस्त मध्यप्रदेश में अगस्त 2026 के दौरान वाहन बाजार में त्योहारी सीजन की तैयारियों, कंपनियों के आकर्षक ऑफर और मानसून की स्थिति का असर दिखाई दे रहा है.

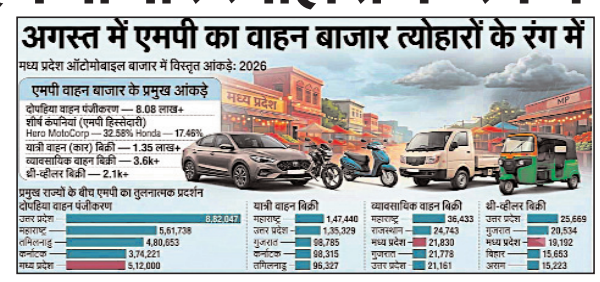

वाहन कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग-अलग मॉडलों पर छूट, वित्तीय योजनाएं और अन्य लाभ दे रही हैं. इससे आने वाले त्योहारी महीनों में वाहन बिक्री बढ़ने की उम्मीद है. देशभर में भी कंपनियां अगस्त से शुरू होने वाले त्योहारी दौर को बिक्री बढ़ाने के महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रही हैं. मध्यप्रदेश में दोपहिया वाहनों की बिक्री बाजार का अहम हिस्सा बनी हुई है. उपलब्ध वाहन पंजीयन आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अगस्त 2026 के दौरान प्रदेश में 8.08 लाख से अधिक दोपहिया वाहनों का पंजीयन हुआ. इनमें हीरो मोटोकॉर्प करीब 32.58 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रहा. होंडा की हिस्सेदारी 24.04 प्रतिशत और टीवीएस की 17.46 प्रतिशत रही. ये आंकड़े वाहन निर्माताओं की बिक्री नहीं, बल्कि आरटीओ में दर्ज वाहन पंजीयन पर आधारित हैं.अगस्त में मानसून की स्थिति भी वाहन बाजार के लिए महत्वपूर्ण है. ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने पर कृषि गतिविधियों और ग्रामीण आय में सुधार से दोपहिया तथा ट्रैक्टर जैसे वाहनों की मांग को सहारा मिल सकता है.

कुल मिलाकर, मध्यप्रदेश के वाहन बाजार के लिए अगस्त से शुरू हुआ दौर आगे आने वाले त्योहारी महीनों की दिशा तय कर सकता है. हालांकि, अगस्त 2026 की अंतिम श्रेणीवार और जिलेवार बिक्री के आधिकारिक आंकड़े पूरी तरह उपलब्ध होने के बाद ही बाजार की सटीक तस्वीर सामने आएगी.

नौकरी छूटने पर कर्मचारियों को मिलेगा 75 प्रतिशत पीएफ

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 28 अगस्त. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि से आंशिक निकासी के नियमों को सरल कर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

नए नियमों के तहत अब अलग-अलग परिस्थितियों में पीएफ की आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को समान करते हुए 12 महीने कर दिया गया है. यानी पात्र कर्मचारी एक साल की सेवा पूरी करने के बाद निर्धारित शर्तों के तहत पीएफ से आंशिक राशि निकाल सकेंगे.

ईपीएफओ ने पुराने 13 अलग-अलग निकासी प्रावधानों को तीन व्यापक श्रेणियों में समेट दिया है. पहली श्रेणी में बीमारी, बच्चों की शिक्षा और शादी जैसी जरूरतों को शामिल किया गया है. दूसरी श्रेणी में घर खरीदने, घर बनाने और आवास ऋण चुकाने जैसे खर्च रखे गए हैं. तीसरी श्रेणी में विशेष परिस्थितियों में निकासी का प्रावधान है, जिसमें सदस्य को अलग से कारण बताने या दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी. नए नियमों के तहत सदस्य अपने पीएफ खाते में उपलब्ध पात्र राशि का 75 प्रतिशत तक हिस्सा निकाल सकेगा.

एआई से जापान का निर्यात उछला

- चार साल में सबसे बड़ी सालाना छलांग
- जुलाई में जापान का निर्यात 23 प्रतिशत बढ़ा
- इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ी

नवभारत न्यूज

नयी दिल्ली, 28 अगस्त कृत्रिम मेधा (एआई) का बढ़ता इस्तेमाल वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव का कारण बन रहा है. एआई से जुड़े उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर की मांग में तेजी का असर अब जापान के निर्यात पर भी साफ दिखाई देने लगा है.

जापान का निर्यात जुलाई में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 23 प्रतिशत बढ़ा. यह अक्टूबर 2022 के बाद से जापान के निर्यात में दर्ज सबसे बड़ी सालाना वृद्धि है. इससे पहले जून में देश के निर्यात में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी. फरवरी से लगातार जापान के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है. जापान लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और तकनीकी उत्पादों के वैश्विक कारोबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है. एआई के तेजी से विस्तार ने इन उत्पादों की मांग को और बढ़ाया है.

खासकर डेटा सेंटर, एआई सर्वर और उन्नत तकनीकी उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मांग बढ़ने से जापानी कंपनियों को फायदा मिला है.

यही वजह है कि निर्यात में लगातार तेजी बनी हुई है. ताइवान और दक्षिण कोरिया पहले ही एआई से जुड़ी वैश्विक मांग का लाभ उठा रहे हैं और अब जापान भी इस दौड़ में मजबूती से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है.

अमेरिका में आर्थिक वृद्धि धीमी

दूसरी ओर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार अप्रैल-जून तिमाही में धीमी पड़ी है. अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अनुसार, इस अवधि में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 1.5 प्रतिशत रही, जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में यह 2.1 प्रतिशत थी. जून तिमाही की वृद्धि दर विभाग के शुरुआती अनुमान के अनुरूप रही. हालांकि वृद्धि दर में कमी आई है, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत उपभोक्ता खर्च और एआई से जुड़े निवेश का सहारा मिला है. अमेरिका की अर्थव्यवस्था में करीब 70 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला उपभोक्ता खर्च अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर 3.4 प्रतिशत बढ़ा. इसके मुकाबले जनवरी-मार्च तिमाही में उपभोक्ता खर्च की वृद्धि केवल 0.5 प्रतिशत रही थी.

5 लाख तक किसान को मिल सकता है क्रेडिट कार्ड लोन

खेती की जरूरतों के लिए बैंक तय करता है क्रेडिट लिमिट

समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर 4% तक हो सकती है

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 28 अगस्त. खेती में बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और दूसरी जरूरी चीजों के लिए किसानों को अक्सर फसल से पहले पैसे की जरूरत पड़ती है. ऐसे में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) किसानों के लिए बैंक से आसानी से कृषि ऋण लेने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है.

इसके तहत किसान को खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए एक तय क्रेडिट सीमा उपलब्ध कराई जाती है. किसान जरूरत के मुताबिक इस सीमा से राशि निकाल सकता है और निर्धारित अवधि में उसका भुगतान कर सकता है. केसीसी के तहत फसल ऋण की अधिकतम सीमा ?5 लाख तक कर दी गई है. हालांकि, हर किसान को सीधे ?5 लाख का ऋण नहीं मिलेगा. बैंक किसान की जमीन, फसल, खेती की जरूरत, अनुमानित खर्च और भुगतान क्षमता जैसे कारकों का आकलन करके ऋण सीमा तय करता है. इसलिए वास्तविक केसीसी सीमा किसान की पात्रता और बैंक के मूल्यांकन पर निर्भर करेगी. केसीसी पर सामान्य रियायती ब्याज दर 7 प्रतिशत बताई गई है. समय पर ऋण चुकाने वाले पात्र किसानों को ब्याज में 3 प्रतिशत की प्रोत्साहन छूट मिल सकती है. इससे प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत तक रह सकती है. हालांकि, यह लाभ लागू सरकारी नियमों और ऋण की पात्र राशि के अनुसार मिलता है.

केसीसी का इस्तेमाल सिर्फ फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है. किसान इसका उपयोग बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और खेती से जुड़े अन्य खर्चों के लिए कर सकते हैं. पशुपालन, डेयरी और मछली पालन जैसी गतिविधियों से जुड़े किसानों को भी कार्यशील पूंजी के लिए केसीसी का लाभ मिल सकता है.

केसीसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान को खेती के मौसम में समय पर संस्थागत ऋण मिल जाता है. इससे महंगे ब्याज पर अनौपचारिक कर्ज लेने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, किसान को अपनी जरूरत और भुगतान क्षमता के अनुसार ही ऋण लेना चाहिए और समय पर किस्त या बकाया चुकाना चाहिए, ताकि ब्याज में मिलने वाली राहत का लाभ मिल सके.

वीआईटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ऐतिहासिक साझेदारी

मुंबई, 28 अगस्त. वीआईटी ने हाल ही में न्यूयॉर्क, अमेरिका स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय (कोलंबिया इंजीनियरिंग) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. यह समझौता ज्ञापन न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्यदूत बिनय श्रीकांत प्रधान की उपस्थिति में वीआईटी के कुलाधिपति डॉ. जी. विश्वनाथन और अकादमिक मामलों और वैश्विक साझेदारी के डीन सेन. सौलेमान कचानी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया.

इस ऐतिहासिक साझेदारी के साथ वीआईटी कोलंबिया विश्वविद्यालय के साथ दोहरी डिग्री कार्यक्रम करने वाला पहला भारतीय विश्वविद्यालय बन गया है, जिससे इंजीनियरिंग छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तरीय शैक्षणिक मार्ग खुल गए हैं.

साझेदारी के महत्व पर जोर देते हुए, वीआईटी के संस्थापक और कुलाधिपति डॉ. जी. विश्वनाथन ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और इस सहयोग को वीआईटी के इतिहास में एक निर्णायक क्षण बताया: 'यह वीआईटी और कोलंबिया विश्वविद्यालय के बीच एक ऐतिहासिक समझौता है.

हमें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक के साथ दोहरी डिग्री कार्यक्रम स्थापित करने वाला पहला भारतीय विश्वविद्यालय बनने पर गर्व है.

निजी कंपनियों की बढ़ी बिक्री

नवभारत न्यूज

मुंबई, 27 अगस्त निजी क्षेत्र की गैर-वित्तीय कंपनियों की बिक्री चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 19.4 प्रतिशत बढ़कर 21,57,098 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी.

रिजर्व बैंक ने गुरुवार को औचक आधार पर चयनित 3,247 कंपनियों के आंकड़ों के आधार पर ये आंकड़े जारी किये हैं. इसमें बताया गया है कि अप्रैल-जून 2026 की तिमाही के दौरान गैर-वित्तीय निजी कंपनियों में विनिर्माण क्षेत्र की बिक्री एक साल पहले के मुकाबले 21.4 प्रतिशत बढ़ गयी. सर्वेक्षण में 1,827 कंपनियां विनिर्माण क्षेत्र से थीं.

आईटी क्षेत्र की बिक्री में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी. वहीं, आईटी से इतर सेवा क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री में 19.7 प्रतिशत का इजाफा हुआ.

समाचार विशेष

यूपी में आज चुनाव हुए तो सपा-भाजपा को कितनी सीटें

नए सर्वे में योगी के सामने बड़ी चुनौती

नवभारत नेटवर्क

लखनऊ, 28 अगस्त. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. सत्ता में साढ़े नौ साल से काबिज भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के बीच एक दूसरे को पटखनी देने के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं.

लुभावने वादे से लेकर आरोप-प्रत्यारोपों का दौर नए मुकाम पर पहुंच चुका है. इस बीच जनता का मूड भांपने के लिए नया सर्वे किया गया है. इस सर्वे ने बीजेपी को हैरान कर दिया है. इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनौती बढ़ गई है. जबकि समाजवादी पार्टी के नेता गदगद हैं और सोशल मीडिया पर सर्वे को शेयर कर अपने पक्ष में प्रदेश का माहौल होने की बातें कह रहे हैं. यूपी से ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता निकलता है. यहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें भी हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में सपा ने भाजपा को तगड़ा झटका दिया था. सपा ने ही बीजेपी के लोकसभा में बहुमत की राह भी रोक दी थी. सपा-कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया था.

इस सर्वे में यह जानने की कोशिश की गई थी कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में सपा को 80 में से 37 और उसकी सहयोगी कांग्रेस को छह सीटें मिली थीं. भाजपा के हिस्से में 33 और सहयोगियों को तीन सीटें मिली थीं. इसमें अपना दल को एक और रालोद को दो सीटें मिली थीं. एक सीट आजाद समाज पार्टी के हिस्से आई थी. नए सर्वे में बीजेपी को 34 सीटें मिलती दिख रही हैं.

मराठी के मुद्दे पर भाजपा की खामोशी

मुंबई. महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सिखाने का अभियान चलाया है. इससे पहले 2017 में राज्य सरकार एक नियम ले आई थी कि मराठी नहीं बोलने वाले ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए.

हालांकि अदालत ने इसे खारिज कर दिया था. उससे पहले और बाद में भी मराठी मानुष की राजनीति करने वाले राज ठाकरे जैसे छोटे मोटे नेता अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए मराठी भाषा के नाम पर ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों से मारपीट किया करते थे. लेकिन पहली बार रा'य सरकार व्यवस्थित तरीके से यह प्रयास कर रही है. पुलिस की सुरक्षा में सरकारी कर्मचारी ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को रोक कर मराठी का टेस्ट ले रहे हैं. सरकार की ओर से बनाए गए नियम के मुताबिक टेस्ट में फेल होने पर उनको एक महीने का समय दिया जाएगा. अगर एक महीने में वे मराठी नहीं सीख पाते हैं तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जाएगी. महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी पार्टियों को इससे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि चाहे एकनाथ शिंदे की शिव सेना हो या सुनेत्रा पवार की एनसीपी, दोनों को सिर्फ वही की राजनीति करनी है.

कल्याण सिंह के करीबी ने थामा बसपा का दामन

मऊ. जनपद मऊ की राजनीति में बुधवार को उस समय हलचल तेज हो गई, जब इटौरा चौबेपुर निवासी प्रसिद्ध व्यवसायी एवं समाजसेवी अजय जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया. उनके बसपा में शामिल होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में उनकी अगली भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

माना जा रहा है कि बसपा उन्हें घोसी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना सकती है. हालांकि, पार्टी की ओर से अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. एक के बाद एक करके लगातार जिले के पुराने भाजपा नेताओं की हाथी की सवारी से जिले में लगातार बसपा का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगातार हो रहे दल बदल से जिले में चर्चाओं का दौर काफी तेज हो गया है और इसे आगामी विधानसभा चुनाव के फायदे और नुकसान से भी जोड़कर देखा जा रहा है. अजय जायसवाल के राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो वो वर्ष 2000 से पहले तत्कालीन भाजपा के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के करीबी लोगों में गिने जाते थे. कल्याण सिंह के भाजपा से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने के बाद वर्ष 2000 में अजय जायसवाल को मऊ जिले की कमान सौंपी गई थी और वह उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे. इस दौरान अजय जायसवाल ने लगातार मऊ के अंदर कल्याण सिंह की पार्टी के वर्चस्व को मजबूत किया.

बदलेगा घोसी का सियासी समीकरण?

अजय जायसवाल के बसपा में शामिल होने के बाद सबसे अधिक चर्चा घोसी विधानसभा क्षेत्र को लेकर है. राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि बसपा उन्हें यहां से चुनाव मैदान में उतार सकती है. हालांकि, अभी तक पार्टी की ओर से टिकट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. यदि अजय जायसवाल को बसपा का प्रत्याशी बनाया जाता है तो घोसी की चुनावी लड़ाई में एक नया चेहरा और नया समीकरण देखने को मिल सकता है. खासकर लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहने और विभिन्न वर्गों के बीच संपर्क को उनकी संभावित उम्मीदवारी की महत्वपूर्ण ताकत माना जा रहा है. अजय जायसवाल के भाजपा छोड़ने से पार्टी की स्थानीय राजनीति पर भी इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है.

विशेष | नीतीश की विरासत पर उपेंद्र कुशवाहा के दांव से मचा बवाल

क्या बिहार में शुरू हो गया शाह का गेम प्लान

पटना. बिहार की सियासी गलियारे में नीतीश विरासत की जंग इन दिनों खास चर्चा का केंद्र बना हुआ है. सवाल तो इस सिलसिले में कई खड़े किए जा रहे हैं, मगर जो सवाल राजनीतिक गलियारों में खास तव्वजो पा रहा है, वो ये कि क्या मोदी.शाह का कहीं गेम प्लान तो नहीं नीतीश विरासत की जंग!

ये इसलिए कि नीतीश की विरासत की जंग की शुरुआत राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से ही शुरू कर दी. बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी उपेंद्र कुशवाहा कुछ खास मौके पर प्रिविलेज पाते रहे हैं. जब राजनीतिक गलियारों में उनके संभावनाओं को ना कहा जाता रहा हो, वो सफल होते दिखे. वो चाहे लोकसभा 2024 हो या बिहार विधानसभा चुनाव 2025. राष्ट्रीय लोक मोर्चा को अपेक्षानुकूल अनुमान से 'यादा हिस्सेदारी मिलती रही है. इसे लेकर अन्य साथी दलों के साथ.साथ भाजपा के भीतर भी काफी कानाफूसी हुई. कई को टिकट से बेदखल होना पड़ा, मगर ये सब होता रहा और उपेंद्र कुशवाहा को जो कुछ पाना था पाते रहे.

तहलका तो तब मचा- लेकिन, तहलका तो तब मचा जब विधानसभा में सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा अपने पुत्र दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने में सफल रहे. वो भी तब जब दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे. आलोचना के दायरे में तब बीजेपी नेतृत्व तो आया ही उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी के भीतर भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. लगा की पार्टी टूट जाएगी. हुआ वही जो बीजेपी नेतृत्व चाहता थाए दीपक प्रकाश मंत्री बने रहे. उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश जब मंत्री बने रहे तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा विशेष होने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा रा'यसभा नहीं जाने के शर्त पर आपने पुत्र को मंत्री बनाया होगा.

फिर मंत्री बने दीपक प्रकाश!

बिहार जब ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा था और विकास पुरुष नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री पद से मुक्त कराया जा रहा थाए तब नए मंत्रिमंडल में दीपक प्रकाश के मंत्री बनने की संभावना लगभग नहीं थी. तब न्यायालय की टिप्पणी भी प्रतिकूल थी. बावजूद दीपक प्रकाश मंत्री बनाए गए. अंततः दीपक प्रकाश के मंत्री पद को जस्टिफाई करने के लिए अपने एमएलसी देवेश कुमार की कुर्बानी देकर उनके मंत्री पद को बचाया गया.